Employee's share is equity for public sector

2339. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Standing Conference on Public Enterprises has recommended a 5 per cent share in equity for public sector employees; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRIES AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b) Government have appointed a Committee to suggest modalities of further disinvestment. The recommendations of the Standing Conference of Public Enterprises have been conveyed to the Committee for its consideration. Final Report of the Committee is awaited.

कपड़ा मिल मशीनरी का निर्यात

2240. **श्री रणजीत सिंह :**
श्रीराम जेठमलानी : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कपड़ा मिल मशीनरी उद्योग में कपड़ा मिल मशीनें निर्यात करने की पर्याप्त क्षमता है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में इन मशीनों का आधुनिकीकरण करके इस क्षमता में वृद्धि की जा सकती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1990–91 और 1991–92 के दौरान कपड़ा मिल मशीनों का निर्यात किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो इन वर्षों में निर्यात की गई मशीनों का अलग-अलग मूल्य कितना है ;

(ङ) निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन मशीनों को आधुनिक बनाने के लिए सरकार की क्या योजना है ;

(च) क्या यह भी सच है कि कपड़ा मिल मशीनरी के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने उदार शर्तों पर ऋण देना बन्द कर दिया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, हां ।

(घ) 1990–91 तथा 1991–92 के दौरान क्रमशः 156 करोड़ रु० और 125 करोड़ रु० की कपड़ा मिल मशीनों का निर्यात हुआ है ।

(ङ) इन मशीनों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना तथा ई पी सी जी योजना के तहत पूंजीगत माल के आयात के अलावा तकनीकी विकास निधि योजना के अधीन पूंजीगत माल, विदेशी प्रौद्योगिकी, रेखाचित्रों और डिजाइनों के आयात की अनुमति देती रही है । सरकार ने औद्योगिक तथा आयात-निर्यात संबंधी उदारीकृत नीतियां भी आरंभ की हैं जिनमें लाइसेंसीकरण प्रक्रियाओं, मात्रा संबंधी प्रतिबंधों और विनियमकारी एवं भेदमूलक अन्य नियंत्रणों को पर्याप्त रूप से समाप्त किया गया है ।

(च) और (छ) कपड़ा मिल मशीनरी सहित चुनिंदा उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए नवम्बर, 1976 से एक उदार ऋण योजना लागू थी । सभी

उद्योगों को ब्याज की रियायती दर पर धन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना में जुलाई, 1980 आधुनिकीकरण योजना के रूप में संशोधन किया गया था। अगस्त, 1990 में यह योजना सामान्य योजना के साथ मिला दी गई थी। आधुनिकीकरण के लिए सहायता को अधिक महत्व दिया जाता है और धन सामान्य शर्तों पर अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है। संसाधन की बाधाओं और वित्तीय संस्थाओं द्वारा पहले से मंजूर किए गए वित्त के कारण अब दिए जाने वाले ऋण केवल सामान्य शर्तों पर उपलब्ध हैं।

Voluntary retirement scheme for P.S.Us.

2341. SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:
SHRIMATI MIRA DAS:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the deatils of voluntary retirement scheme for Public Sector Undertakings;

(b) what are the numbers of workers covered by this scheme during the last two years and what is the total quantum of compensation paid to them;

(c) what is the average compensation per workers and what is the average salary of the worker;

(d) whether it is a fact that 19 sick PSEs as reported in the Hindustan Times stated 14th July, 1992 suffered loss of Rs. 194 crores and Rs. 237 crores in 1990-91 and 1991-92 respectively;

(e) if so, what is the accumulated loss so far;

(f) what is the total sum required as retrenchment compensation for all the 19 sick units;

(g) what would be the average compensation per worker;

(h) what are the reasons for losses; and

(i) whether workers are prepared to take any of the sick Public Sector Enterprises on cooperative?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRIES AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON): (a) The model VR Scheme which was evolved by the Govt. in October, 1988 *inter-alia* envisages that the following benefits would be admissible to the employees opting for VR Scheme:—

(i) the balance in his Provident Fund Account payable as per the CPF regulations.

(ii) cash equivalent of accumulated earned leave as per the rules of the enterprises.

(iii) gratuity as per Grauity Act or the gratuity scheme applicable to the employees.

(iv) one month's/three months' notice pay (as per the conditions of service applicable to him).

(v) an *ex-gratia* payment equivalent to $1\frac{1}{2}$ months emoluments (pay+DA) for each completed year of service or the monthly emoluments (pay+DA) at the time of retirement multiplied by the balance months of service left before the normal date of retirement, whichever is less.

(vi) the employee and his family would also be entitled to travel by the entitled class to the place where he intends settling down.

(b) and (c) The assessment about the number of employees who would be considered surplus to the requirement of the PSE has to be made by the PSE itself. The exact number of employees who could be categorised as surplus in each PSE is, therefore, not available. The expenditure which will be incurred by a PSE which has already notified surplus manpower is also required to be assessed by the said PSE having regard to the pay scale in which such employees are working, the actual basic pay and DA drawn by them, the length of service